विनिर्माण उद्योग में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग

*186. **श्री रवि शंकर प्रसाद**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक सुधारों के संदर्भ में बनाई गई नई औद्योगिक नीति, 1990 के कार्यान्वयन के पश्चात् देश में विनिर्माण उद्योग में पूंजी प्रधान प्रौद्योगिकी के उपयोग को बल मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि विनिर्माण उद्योग में श्रम घटक की लागत वर्ष 2005 से अब तक उतनी ही बनी हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) 1991 की औद्योगिक नीति, क्षमता निर्माण की बाधाओं को दूर करने तथा औद्योगिक लाइसेंसीकरण को समाप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई थी ताकि भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, अधिक दक्ष तथा आधुनिक बनाया जा सके। नई नीति के अनुसार, प्रौद्योगिकी चुनाव और पूंजी के उपयोग संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा अपनी वाणिज्यिक समझ के अनुसार लिए जाने थे। अलबत्ता, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार संगठित विनिर्माण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति नियोजित पूंजी (स्थिर मूल्यों पर) 1993-94 के 3.6 लाख रुपए से बढ़कर 2008-09 में 6.7 लाख रुपए हो गई। नवीनतम आंकड़े वर्ष 2008-09 तक ही उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) संगठित विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2004-05 से, कुल उत्पादन लागत के प्रतिशत के तौर पर श्रम की लागत नीचे दी गई है:—

वर्ष	संगठित विनिर्माण क्षेत्र में कुल उत्पादन लागत के प्रतिशत के तौर पर श्रम की लागत
2004-05	4.2
2005-06	4.3
2006-07	4.1
2007-08	4.3
2008-09	4.3

Use of capital-intensive technology in manufacturing industry

†*186. SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Will the Minister of COMMERCE AND INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that use of capital-intensive technology has gained force in the manufacturing industry in the country after the implementation of New Industrial Policy, 1990, formulated in the context of economic reforms;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that the cost of labour component of manufacturing industry has remained static since 2005 so far; and

(d) if not, the facts in this regard?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ANAND SHARMA): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Industrial Policy of 1991 was designed to remove restraints on capacity creation and abolish industrial licensing to make Indian industry more competitive, more efficient and modern. Decisions with regard to the choice of technology and capital use, in the new policy were to be taken by the entrepreneurs based on their commercial perceptions. As per the Annual Survey of Industries (ASI), however, capital employed per person (at constant prices) engaged in organized manufacturing sector has increased from Rs. 3.6 lakh in 1993-94 to Rs. 6.7 lakh in 2008-09, the latest year for which the data is available.

(c) and (d) The cost of labour as percentage to the total cost of production, in organized manufacturing sector since 2004-05 is indicated below:—

Year	Cost of labour as percentage to the total cost of production in organized manufacturing sector
2004-05	4.2
2005-06	4.3
2006-07	4.1
2007-08	4.3
2008-09	4.3

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री जी, मैंने आपका उत्तर देखा है। आपने 1991 की उद्योग नीति की चर्चा की है कि उद्योग में, विशेष रूप से निर्माण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा हो और दक्षता बढ़े। उसमें आपने यह भी लिखा है कि प्रति व्यक्ति नियोजित पूंजी अब काफी बढ़ गई है। इतना सब करने के बावजूद ऐसा क्यों है कि विगत दो-तीन वर्षों में उद्योग का जो निर्माण क्षेत्र है, मैन्यफैक्चरिंग सेक्टर है, इसमें गिरावट आ रही है? इसमें गिरावट के क्या कारण हैं? वाणिज्य और उद्योग मंत्री के रूप में आपको क्या लगता है, जबकि सबसे अधिक नियोजन देने वाला क्षेत्र यही है?

श्री आनन्द शर्मा: सर, माननीय सदस्य का प्रश्न कैपिटल इन्टेंसिव टेक्नोलॉजी से सम्बन्धित है, मैन्यफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अन्दर, जिसका मैंने सही उत्तर दे दिया है। जहाँ तक मैंने पिछले 20 वर्षों की नीति की

चर्चा की है, तो 1991 में देश में इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी, जिसमें लाइसेंसिंग की पुरानी प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। राज्य ने केवल दो सेक्टर्स, रेलवेज़ और एटॉमिक इनर्जी, अपने पास रखे और केवल पाँच अन्य सेक्टर्स में लाइसेंसिंग जारी रखी। वे जो सेक्टर्स हैं, उनका भी मैं उल्लेख कर सकता हूँ। परन्तु, महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों में वृद्धि हुई है। जहाँ तक पूँजी निवेश की बात है और उसके साथ-साथ मुलाजिमों की संख्या की बात है, इन दोनों में बढ़ोत्तरी हुई है, यह नहीं कि कैपिटल इन्टेंसिव इंडस्ट्रीज़ के बनाने से इम्प्लायमेंट में कोई कमी आई है। जहाँ तक मैन्यफैक्चरिंग की स्पेसिफिक बात इन्होंने पूछी है, तो हमारी जी.डी.पी. में मैन्यफैक्चरिंग का हिस्सा कम है, जोकि एक चिन्ता का विषय है। वह पिछले बीस वर्षों से 16 प्रतिशत पर रुका हुआ है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि वह 16 प्रतिशत पर ही रुका हुआ है और इसके माने यह है कि वह बढ़ा नहीं, पर हमारी जी.डी.पी. भी बहुत बढ़ गई है। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। हमने एक नई नीति लाने का उल्लेख मैन्यफैक्चरिंग पॉलिसी के माध्यम से किया है। हमारे बराबर की या हमारे से कम्परेटिव जो इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पर जी.डी.पी. में 26 प्रतिशत से लेकर 33 प्रतिशत तक मैन्यफैक्चरिंग का हिस्सा है और हमारी भी यह कोशिश रहेगी कि इसको बढ़ाया जाए।

सर, इन्होंने उससे जुड़ा जो दूसरा सवाल किया कि क्या औद्योगिक उत्पादन में कमी आई है, तो मेरा कहना है कि औद्योगिक उत्पादन में कमी नहीं आई है। 2008-09 में जब विश्व के अन्दर एक भारी आर्थिक संकट आया था, तब औद्योगिक उत्पादन कम हुआ था और केवल एक महीने के लिए बहुत कम मात्रा में, जो निगेटिव क्षेत्र है, उसमें औद्योगिक उत्पादन गया। जून, 2009 से उसकी वापसी हुई और 2009 का जो वर्ष था, वह खत्म किया। पिछले 15 वर्षों में सबसे ज्यादा औद्योगिक उत्पादन भारत ने रिकॉर्ड किया। चूँकि बेस ईयर का इफेक्ट होता है, 2009 में इसमें 18 प्रतिशत और मैन्यफैक्चरिंग में 20 प्रतिशत जहां विकास हुआ, इसको बेस मानते हुए भी हमारा औद्योगिक उत्पादन निरन्तर बढ़ रहा है और पिछले वर्ष भी, जो 2010 का है, जो सालाना औसत है, वह 8.6 प्रतिशत है। हमारा हर तरह से प्रयास है कि निवेश भी बढ़े रोजगार भी बढ़े और औद्योगिक उत्पादन भी बढ़े।

श्री सभापति: थैंक यू। दूसरा प्रश्न।

श्री रवि शंकर प्रसाद: माननीय मंत्री जी, आपने औद्योगिक क्षेत्र के बारे में जो आशावादी चित्र अभी रखा, आपके आर्थिक सर्वे से उसका संकेत नहीं मिलता, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। इसकी चर्चा मैं कभी आपसे अलग से करूँगा।

श्री आनन्द शर्मा: देखिए, मेरे पास आँकड़े हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: आप इनका सवाल सुन लीजिए।

श्री रवि शंकर प्रसाद: मैं इस पर आपसे अलग से बहस करूँगा।...(**व्यवधान**)... अभी मेरा आपसे दूसरा सवाल है। आपने कहा है कि उत्पादन लागत के प्रतिशत के तौर पर श्रम की जो लागत है, उस बारे में आपने आँकड़े दिए हैं। अगर आप 2004-05 से 2008-09 देखिए तो यह 4.2 से 4.3 के बीच में ही है। अभी आपने स्वयं स्वीकार किया कि जी.डी.पी. में औद्योगिक निर्माण क्षेत्र का योगदान 16 प्रतिशत पर ही स्थिर है। ऐसी परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकालना कि श्रमिकों की भागीदारी और उन पर जो निवेश हो रहा है, वह भी बहुत संतोषजनक है, इस निष्कर्ष का आपका आधार क्या है?

श्री आनन्द शर्मा: सर, मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूँ कि कैपिटल इन्टेंसिव इंडस्ट्रीज़ के अन्दर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसमें हाई टेक्नोलॉजी आती है, उसमें उच्च स्तर की मशीनरी लगती है, जिससे वहाँ पर जो मुलाजिम हैं या लेबरर्स हैं, वे बड़ी मशीनों पर काम करके और आधुनिक टेक्नोलॉजीज़ को प्रयोग में लाकर उत्पादन बढ़ाते हैं। उसमें लेबरर्स की संख्या नहीं बढ़ती।

हमारे यहाँ जो कैपिटल इन्टेंसिव उद्योग लगे हैं, जो और भी लगने चाहिए, तभी जीडीपी में मैन्यफैक्चरिंग के हिस्से को बढ़ाने की जो बात है, वह पूरी हो पाएगी। उसमें लेबरर्स की संख्या उसके बाद भी बढ़ती जा रही है। आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1990-91 में उद्योग में 1,94,913 करोड़ रुपये लगे थे और आठ करोड़ से ज्यादा लोग यानी 82.79 मिलियन लेबरर्स की संख्या थी। अब उसमें पूंजी निवेश 15,35,178 करोड़ रुपये हैं तथा लेबरर्स की संख्या 113.27 मिलियन है। इस प्रकार, उसमें लेबरर्स की संख्या 31 मिलियन बढ़ी है और पूंजी का निवेश भी बढ़ा है।

एक अन्य बात को भी मद्देनजर रखना आवश्यक है कि मैन्यफैक्चरिंग का शेयर बढ़ाने के लिए अपने देश या बाहर के देशों के लोग, जो निवेश करते हैं, उनको यह निर्णय करना होता है कि उस सेक्टर के अंदर वे कौन-सी तकनीक चाहते हैं या वे उसमें कौन-सी मशीनरी लगाना चाहते हैं। हमारी ऐसी मान्यता है कि मैन्यफैक्चरिंग की नयी नीति, जिसका उल्लेख माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में भी किया है और सरकार ने इस मैन्यफैक्चरिंग-नीति को लाना तय कर लिया है, उससे हमारा मैन्यफैक्चरिंग बढ़ेगा तथा यह जो आंकड़ा मैंने आपको दिया, आने वाले वर्षों में share of GDP में बड़ा परिवर्तन होगा।

DR. ASHOK S. GANGULY: Sir, with the increase in intensity of capital investment, both in capital intensive industries as well as industries in general and in the service sector, and commensurate increase in employment as well, the measure for effectiveness of those investments is total fact of productivity. Does the hon. Minister have any broad figures for improvement in total fact of productivity without which the increase in the proportion of manufacture in the total GDP would be diluted rather than incremental?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the question which was put to me was regarding the capital intensive technologies. The details of productivity of individual sector is not related to this question. I can only say that the industrial productivity in general terms is, the hon. Member is very knowledgeable, increasing because those who are investing in technology, investing in capital are ensuring that the productivity is higher and we become globally competitive.

As far as the increase in productivity is concerned, there will be a better utilization; I agree that the increased productivity, better utilization of both the capital as well as the labour is good. I can send the details of sector-wise productivity. I would only add one thing here, Sir. When we talk of capital intensive and induction of technologies, the House would appreciate that India being a very populous country of close to 1.2 billion, and in the coming one decade another 100 million young Indians would be joining the workforce, therefore, we have to ensure that manufacturing grows, productivity grows and we ensure that there is gainful employment available in the industrial sector for this large number of workforce.

MS. MABEL REBELLO: Sir, the Minister has referred to the population increase. Sir, India being a large country, unless we remain a manufacturing country, our educated youth will remain unemployed and under-employed. On skill development also we are giving importance and it has not spread to the whole country. Because of this problem, our youth are going to anti-social

elements and naxals. How does he try to improve the manufacturing sector so that the youth in the rural areas, especially in the tribal areas of the central India, do not go to naxals but remain in the mainstream? I would like to know about this from the hon. Minister.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, the first part of the question is very important, and I thank the hon. Member, Ms. Mabel Rebello for raising it. When it comes to the manufacturing, I think, hon. Chairman, Sir, the House will agree that I have answered it in great detail as to what we propose to do to increase the share of manufacturing. ...*(Interruptions)*...

MS. MABEL REBELLO: You have not answered my question about rural areas and tribal areas.

MR. CHAIRMAN: Please, please. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Second thing, Sir, the Government, as such, makes a policy regime whether it is for FDI and other related issues for the industrial sector. Industry, as such, is also a State subject and the zoning of the land, earmarking a particular area as an industrial region is not done by the Union Government but by the State Governments. Certainly, Sir, efforts are there by the Government of India to ensure that young people, both in urban areas, and particularly, in rural areas and tribal areas, are trained in skills because the employment opportunities which will be generated with the industrial expansion can only be gainfully utilized if we train our people, make them employable in industrial skills by training them which have multiple industrial applications. So, the National Mission was announced by the hon. Prime Minister. He Chairs the Prime Minister's Council on Skills Training. We have a National Skills Training Corporation, and it has come up with many modular initiatives to ensure that 500 million Indians get trained in skills and in vocational education by 2022. Sir, 1500 new IITs are being set up in the country.

SOME HON. MEMBERS: ITIs, not IITs. ...*(Interruptions)*...

SHRI ANAND SHARMA: Sorry, that is just a slip of tongue. ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: Yes, Please.

SHRI ANAND SHARMA: I said that 1500 ITIs are being set up throughout the country. This will be in addition to 7900 ITIs which already exist in the country. Besides that, sector specific initiatives have been taken. The Labour Ministry is coordinating this. Even in my Ministry, in partnership with the industry, we have brought in some training modules from other countries, entering into meaningful agreements, particularly for skills training in the industrial clusters, and I can send all the details. But about where the employment is increasing, I think, the hon. Member needs to address that question to the Labour Ministry.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, the number of unemployed people in this country keeps on going up. In reply to a separate Question, I have the figures here, that as of 31st December, 2010, the total number of job-seekers registered with the employment exchanges was 3.88 crores. And yet, Sir, this Government keeps on incentivizing big industry, which is capital intensive, and tax concessions are given to them, which are denied to the Small Scale Industries, which is labour-intensive industry.

MR. CHAIRMAN: Question, please.

SHRI NARESH GUJRAL: Sir, my question is that on R&D, weighted deduction is given to Auto Industry and Pharma Industry but is denied to jewellery, to handicrafts, to garments. Would the Government consider giving these incentives to Small Scale Industries also?

SHRI ANAND SHARMA: Sir, in the Budget, the Finance Minister has announced enhanced weighted deduction on payments made to national laboratories, Universities and Institutes of Technologies for scientific research from 175 per cent to 200 per cent. That means, for research and development. When it comes to the MSME Sector, Sir, the Government has a number of schemes to support this Sector, including credit from the SIDBI. Besides that, there is also a Capital Subsidy Scheme for the Micro, Small and Medium Enterprises Sector. It is not true that most of the growth is coming from the heavy industries sector. MSME Sector accounts for 40 per cent of our exports and almost in the same range when it comes to percentage terms to industrial production.

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Implementation of Contract Labour (Regulation and Abolition) Act

*187. SHRI MOINUL HASSAN: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether major action is yet to be taken to implement under the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act;

(b) whether the implementation of the said Act is limited only to a few States; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): (a) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 is being implemented. The Act is enforced by the organization of the Chief Labour Commissioner (Central), Ministry of Labour and Employment in the central sphere.